

प्रवर्तन नदिशालय प्रमुख के कार्यकाल वसितार पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

प्रलिमिस के लयि:

[वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम \(FEMA\), 1999](#); [धन शोधन नवारण अधनियिम \(PMLA\), 2002](#); [सर्वोच्च न्यायालय](#); [प्रवर्तन नदिशालय](#); [केंद्रीय सतरकता आयोग अधनियिम, 2003](#); [दलिली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम, 1946](#); [परमादेश \(Mandamus\)](#), धन शोधन

मेन्स के लयि:

प्रवर्तन नदिशालय (ED) की संरचना और कार्य

चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [प्रवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) के नदिशक को नरिधारति कट-ऑफ तथि से परे दयि गए दो कार्यकाल वसितार को "कानूनी रूप से वैध नहीं" घोषति कयि है।

- यद्यपि न्यायालय ने नदिशक को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी, लेकनि इससे उनका समग्र कार्यकाल कम हो गया।

मामले की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान नदिशक को **नवंबर 2018** में दो वर्ष की अवधि के लयि नयुक्त कयि गया था। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लयि बढ़ा दयि गया था, जसि बाद में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
 - वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारजि कर दयि था, लेकनि एक वशिषिट परमादेश जारी कयि था जसिमें आगे के वसितार पर रोक लगाई गई थी।
- बाद में सरकार ने स्वयं को तीन वर्षीय कार्यकाल वसितार की शक्तियाँ प्रदान करने के लयि [केंद्रीय सतरकता आयोग अधनियिम, 2003](#) और [दलिली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम, 1946](#) में संशोधन कयि।
 - संशोधनों को यह तरक देते हुए चुनौती दी गई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पछिले नरिदेश का खंडन कयि है जसिमें **CBI प्रमुख (वनीत नारायण केस)** जैसे शीर्ष अधिकारियों के लयि नश्चिती कार्यकाल की वकालत की गई थी।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि संशोधन संवैधानिक थे, लेकनि ED के नदिशक को दयि गए वशिषिट वसितार को अमान्य घोषति कर दयि, क्योंकि उन्होंने पहले के [परमादेश](#) का उल्लंघन कयि था।

नोट: ED नदिशक की नयुक्त **CVC अधनियिम, 2003** की धारा 25 के तहत की जाती है। केंद्र सरकार एक चयन समतिकी सफिरशि पर ED के नदिशक की नयुक्त करती है। समति में **CVC अध्यक्ष, सतरकता आयुक्त, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और केंद्र सरकार के वतित मंत्रालय के सचवि** शामिल हैं।

परमादेश:

- परमादेश कसिी सार्वजनिक नकिय, न्यायाधिकरण, नगिम या नचिली अदालत द्वारा जारी एक रटि या आदेश को संदर्भति करता है, जो उन्हें एक वशिषिट कानूनी करतव्य नभाने का नरिदेश देता है जसि पूरा करने के लयि वे बाध्य हैं।
 - यह लैटिन शब्द से लयि गया है जसिका अरथ है "हम आदेश देते हैं"।
- भारत में इसका उपयोग नागरिकों के **मौलिक अधिकारों** को लागू करने के लयि कयि जाता है जब राज्य या उसकी संस्थाओं द्वारा उनका उल्लंघन कयि जाता है। इसका उपयोग प्राधिकारियों द्वारा शक्तिया वविक के दुरुपयोग को रोकने के लयि भी कयि जाता है।
 - यह भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा क्रमशः संवैधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतगत ही जारी कयि जाता है।

प्रवर्तन नदिशालय (ED):

■ परिचय:

- ED एक बहु-वषियक संगठन है जसि [मनी लॉन्ड्रिंग](#) के अपराधों के साथ [वदिशी मुद्रा कानूनों](#) के उल्लंघन की जाँच करने का अधिकार है।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व वभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होता है।

■ स्थापना:

- वर्ष 1956 में वनिमिय नयित्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के वभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
- वर्ष 1957 में इस यूनटि का नाम बदलकर 'प्रवर्तन नदिशालय' कर दिया गया।
- वर्ष 1960 में इस नदिशालय के प्रशासनिक नयित्रण का कार्यभार आर्थिक मामलों के वभाग से राजस्व वभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दिया गया था।

■ प्रवर्तन नदिशालय के कानून:

- प्रवर्तन नदिशालय नमिनलखिति कानून लागू करता है:
 - [वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम, 1999](#) (Foreign Exchange Management Act- FEMA)
 - [धन शोधन नविरण अधनियिम, 2002](#) (Prevention of Money Laundering Act- PMLA)
 - भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधनियिम, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act- FEOA): यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।

■ संरचना:

- प्रवर्तन नदिशालय का नेतृत्व प्रवर्तन नदिशक द्वारा किया जाता है, इसका मुख्यालय नई दलिली में है।
- मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दलिली में स्थिति पाँच क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन नदिशक द्वारा की जाती है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-on-tenure-extensions-of-enforcement-directorate-chief>

